



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105]
No. 105]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1982/ज्यैष्ठ 10, 1904
NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 1982/JYAISTHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 28-आई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

विषय:—1.5 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन उड़ीसा राज्य बिजली
बोर्ड की हीराकुद हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए
माल और सेवाओं के आयात के लिए लाईसेंस गतें।

सी० सं० आई० पी० सी०/23(29)/82:— उड़ीसा राज्य बिजली
बोर्ड की हीराकुद हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए
1.5 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन आयात लाईसेंस के निर्गमन को
नियंत्रित करने वाली जैसी गतें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में
दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

मणि नारायणस्वामी,
मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 28-आई० टी०
सी० (पी एन)/82 दिनांक 31 मई, 1982 का परिशिष्ट

आयात की बिबेसी अधिक सहकारी निधि (आई ई सी एक) द्वारा प्रदान
किए गए 1.5 बिलियन येन ऋण के अधीन उड़ीसा राज्य बिजली

बोर्ड की हीराकुद हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए
माल के आयातों और सेवाओं के संबंध में लाईसेंस गतें।

खंड:-1

सामान्य गतें

1(1) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड (ओ०एम०ई०बी०) की हीराकुद
हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना की आवश्यकताओं के निस्त-दान के लिए
जापान की विदेशी अधिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एक०) द्वारा
प्रदान किया गया 1.5 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए
खुला है। तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधि-आप्त की जाने वाली
वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों
से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस ऋण के प्रनर्तन पात्र ओत
देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मर्चों और उन्हीं मूल्य के नि.
लाईसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महा निदेशानय, तकनीकी
विकास/पूँजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई
हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाईसेंस (सी०)
का मूल्य 1.700 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) में अधिक नहीं होना
चाहिए।

आयात लाईसेंस का खपत में मुख्य राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधि-
सूचित विनियम दर और आयात लाईसेंस जारी करने की तिथि को प्रकलित

(ग) जहां अधि-प्राप्ति में शामिल घनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिन-ब-दिन न ले या औपचारिक खुली अन्तराष्ट्रीय संविदा के फायदे शांति-प्रशासकीय भाग में महात्त्वपूर्ण हों।

(घ) ऊपर (क) (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तराष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया की अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर संकेतित मामलों में, निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस क्रम में अपनाई जाए, जिसमें जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुगमन हो सके :-

- (1) औपचारिक चुनिन्दा अन्तराष्ट्रीय निविदा करना।
- (2) अनौपचारिक अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।
- (3) एक संभरक में सीधा क़द विशेष कारण, औचित्य लगाने वाली बाधियों के।

ओ० एम० ई० बी० द्वारा सभी नॉटिंग और बोलीकारों के लिए अनुवेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विनिर्दिष्ट और डाह्य बोली विश्लेषण की रिपोर्टें, संविदा देने के प्रस्ताव और बोली लगाने से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों की तीन प्रतियों के साथ चिन्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को तुरन्त प्रस्तुत की जानी चाहिए जो वे सभी दस्तावेज श्रृण करार की अनुसूची -5 की कंडिका 1(2) में दिए गए के अनुसार इनकी पुनरीक्षा के लिए ओ० ई० सी० एफ को भेजगा।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नामों भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1981-82 के लिए ओ० ई० सी० एफ येन फ्रेडिट (परियोजना महायत्ना) य० आर्टिडी पी- 16 के अधीन खोले गए आपरिवर्त्तीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाता चाहिए, जिसका ब्यौरा सीधे खंड 6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाईसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन कृष्ट विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाईसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद दित मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेता चाहिए।

2(6) संभरक की पात्रता: संभरक पात्र स्रोत देशों का नागरिक या पात्र स्रोत देशों में समाविष्ट और पंजीकृत व्यक्ति व्यक्ति है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

2(7) संविदा में घोषणा: प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा:-

"मैं अधोहस्ताक्षरी एवम्प्रमाणित करता हूँ कि संभारित किया जाने वाला मातल-----में (पात्र स्रोत देश) उल्लिखित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों में आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है:-

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क

----- × 100"

संभरक का जहाज पर नि० शुल्क मूल्य

और

"मैं अधोहस्ताक्षरी एवम्प्रमाणित करता हूँ कि ----- (पात्र स्रोत देश का नाम) में ----- (कंपनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

2(8) अपात्र स्रोत देशों में अनुमेय आयात: जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है, उसका चिन्त-दान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मद-वार आधार पर आयातित भाग 30% प्रतिशत से कम हो :-

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क

----- × 100"

संभरक का जहाज पर नि० शुल्क मूल्य

खण्ड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें।

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए:-

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ) के बीच ओ० एम० ई० बी० द्वारा कउड हाईड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन फ्रेडिट आई बी० पी 16 (परियोजना महायत्ना) से संबंधित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए श्रृण समझौते के अनुसार होने चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ) के बीच येन फ्रेडिट म० आर्टिडी पी- 16 में संबंधित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए श्रृण समझौते के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्त्तीय साख-पत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ० ई० सी० एफ द्वारा येन श्रृण के अधीन प्रेषित हों।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होती चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल मातल की सुपुर्गों के कार्यक्रम में अवगत करेगा और पोत-नदान से कम से कम 1 मन्त्रा पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा, जिसमें कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोत-नदान के पश्चात् आवश्यक न्योत्र देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होता चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-4 विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ० ई० सी० एफ) द्वारा ठेके का अनुमोदन:-

4(1) लाईसेंस-धारी की पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ओ० एम० ई० बी० और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विशिष्ट हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियाँ जो विदेशी संभरक द्वारा लिखित में पण्डित आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियाँ संगत वैध आयात लाईसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, चिन्त मंत्रालय, नाथ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

1(2) उपयुक्त किय-विधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विशिष्ट वस्तु के लिए अतिरिक्त आशाओं के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जापान अनुभाग, ओ० ए० ई० बी० के हीराकुड हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए येन केडिट सं० आई० बी० पी०-16 (परियोजना सहायता) के अंतर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ० ई० सी० एफ०) को संविदा स्थापित करने की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान साख पत्र किया विधि.

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ० ई० सी० एफ०) के डेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा ओ० ए० ई० बी० और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद ओ० ए० ई० बी० को सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी० ए० ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक इंडिया, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध 3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी० ए० ए० खंड एण्ड अनुबंध-4 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए) या अनुबंध-6 (सेवाओं के लिए) के रूप में संलग्न प्रपत्र में संबंधित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिए जारी करेगा। प्राधिकार-पत्र की प्रतियाँ (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (ओ० ई० सी० एफ०) भारतीय कूतावास, टोकियो भारत में आयात के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

5(2) प्राधिकारपत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ओ० ई० सी० एफ० भारतीय कूतावास, टोकियो भारत में आयात के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी० ए० ए० ए० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख-पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त किया विधि संविदा संगठित या अन्यथा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के मणोधर्तों पर स्वयं लागू होगी।

5(3) माल का पोत-संचालन करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दुस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो स्थापित करने में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिवृत्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख-पत्र के अंतर्गत सौदे तय करने के लिए, साख-पत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुनाए जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरक के बैंक के प्रभारों के लिए और विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के, भुगतान की तिथि से ओ० ई० सी० एफ० द्वारा प्रतिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए खड़ा किए जाने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग धूल के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा।

खंड-8 क्या निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकारपत्र के परिणाम में संकलित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंक को परकाय्य जहाजगती दस्तावेज भेजना और बैंक इनके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजगती दस्तावेज गिरा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रूपया निक्षेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समतुल्य रूप पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक और उसके अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक होगी, जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक का भुगतान की तिथि से वास्तविक रूपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन) /76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिन अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रकमा जमा किया गया है का ब्याज लिया जाएगा, देखिए, सार्वजनिक सूचना सं० 103 आई टी सी (पी० एन) /78 दिनांक 12-10-76 के अंतर्गत संगठित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी० एन) /74 दिनांक 13-5-1974। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रूप की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की नई मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई टी सी (पी० एन) /74 दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई टी सी (पी एन) /76, दिनांक 17-1-1976 में निर्धारित तरीके के अनुसार निर्धारित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रूपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एंड एक्वासिस्-843 सिविल डिपोजिट्स- डिपोजिट्स फार परचेजिंग एटस्ट्रा एंडोड परचेजिंग अंडर क्रेडिट्स/लोन एप्रीमेंट मोन फ्रीम डि गवर्नमेंट आफ जापान-4 विलियन येन केडिट सं० आई० बी० पी० 16 फार हीरा कुट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट" होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की भाष में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी० एन) /88, दिनांक 30-8-1968, सं० 233-आई टी सी (पी० एन) /88, दिनांक 24-10-1968 सं० 132 आई टी सी (पी एन) /71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन) /74 दिनांक 81-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी० एन) /76 दिनांक 12-10-76 में स्थाननिर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबंध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अनिवार्य धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजना जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। खानान के विभिन्न कालों को भरने समय आयातकों/ उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय हो लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन) /76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़े जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन) /71, दिनांक 5-10-1971 के पैग-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन) /74 दिनांक 21-5-74 में भी निर्धारित सूचना चानान के कलम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ध्येय" में निरपवाद रूप से निविष्ट किए गए हैं। खजाना खानान में निम्नलिखित व्योम निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार-पत्र सं० और विभाग

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परि-
वर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं,

(ग) विदेशी संभरक की भुगतान करने की तिथि

उनके पचात्सी० ए० ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र का संवर्ध देते हुए और बीजक तथा पोत-परिवहन दस्तावेजों को गलत करते हुए खजाना चानान रुपया जमा करने का साधन देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:- भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो में आयातकी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत-लवान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लार्डसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पुष्टीकृत करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बंबई को भेजना चाहिए।

अनुच्छेद-8 विविध व्यवस्थाएं :

8(1) आयात लार्डसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोत-लवान और उसके अधीन किए गए भुगतान और जेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के साथ एक मासिक रिपोर्टें ग्राह्यता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक इंडिया, संयुक्त मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) संभरकों का विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना : लार्डसेंसधारी का आयात लार्डसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो भान के लाने लेजाने में संभरक पर प्रभाव डालती हैं।

8(3) विवाद : यह समझ लेना चाहिए कि लार्डसेंस और संभरको के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर-दायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों अनुबंध-3 में "भुगतान की शर्तों" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए। संविधा की शर्तों में विवाद के निपटान से संबद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

8(4) भविष्य अनुदेश : आयात लार्डसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जागरूक प्राधिकारियों के साथ येन कोडिड समझौते पण्य (यस्तु सह्यता) सं० आई डी पी 16 के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लार्डसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन : उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर प्राधान-नियम (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबंधों की सूची :

1. अनुबंध-1 पात्र खोन देशों की सूची
2. अनुबंध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग-दर्शन
3. अनुबंध-3 अधिप्राप्त जारी करने के लिए अनुबंध
4. अनुबंध-4 अधिप्राप्त का प्रपत्र
5. अनुबंध-5 साख-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबंध-6 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए)।

पात्र खोन देशों की सूची

(क) विजयमशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग से भिन्न विजयमशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी महासागर

मिस्र
मॉरीशस
तुर्मागिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी महासागर :

अंगोला
बंजुला
बुरुंडी
कैमेरून
कंग वर्री दूर्वाग समूह
केन्द्रिय अफ्रीका गणतन्त्र
चाद
कमीरो बीग समूह
कांगो, दाहोम का गणतन्त्र
मध्य गिनी (1)
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
ग्राइबेरो कोस्ट
कोनिया
नेसीथो
नाइजीरिया
मालायासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारिटेनिया मारीशन
सुजम्बिक
नाइजर
पुर्तगाली गिनी
रियूनियम
रॉडेशिया
रवाण्डा]
सेंट हेल्जिना और डेप (2)
नायरोबी और प्रिन्सिप
सेनेगल
सेचिलेज
मियारा मिश्रान
सोमालिया
सूडान
स्वाजिलैण्ड
टेरी आकरा और इस्थाम
टोंगा
गुयाम्था
तशानिया गणतन्त्र संघ
प्रपर बोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय :

बेल्जियम
बार्बाडोस
बेलारुस
बदमूडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतन्त्र
एल साल्वडोर
गुवाडे लोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डुरस
जमैका
मार्टिनिक्
मेक्सिको
मोडर लैण्ड एन्टिलीज
निकारागुवा
पनामा
सेन्टर रिपब्लिक और निकेजान
ट्रिनिडाड और टोबैगो
वेस्ट इन्डीज (शाखा) एनमार्ईई
(क) सह-संबद्ध राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरलेन्डा पां द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—

अक्सेन्शन, ट्रिस्बन्डा इन एन्सोमिबिस्म, नाइटिन्सेल गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह अरूबा, बोनाइरे क्यूराकाओं साहा, सेन्ट यूस्टासिय
सेन्ट मारटिन (दक्षिणी भाग)

4. दक्षिणी अमेरिका :

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फोल्क लैंड द्वीप समूह
फ्रांसिनी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरू
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्यपूर्वी एशिया :

कैहरान
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
प्रोमन
सिरियाई अरब गणतन्त्र
यूनाइटेड अरब एमिरात (3)
यमन अरब गणतन्त्र
यमन जनवादी का ओ० प्र० (4)

6. दक्षिणी एशिया :

अफगानिस्तान
बांग्ला देश
भूटान
बर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया :

ब्रुनी
हांगकांग
खमैर गणतन्त्र
कोरिया गणतन्त्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतन्त्र
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिनी पोलिनेशिया (5)
नीदर
न्यू कैलेडोनिया
न्यू द्वीपसिस्म (त्रि, ओर फ)
मियू
पोलिनिश द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (बा०)
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समोआ

9. यूरोप :

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, बार्मिनिक्का; प्रैमैडा. सेन्ट फिट्स (सेन्ट फिट्सको) नेमिन्-प्रंगुइला, सेन्ट लूसिया और सेन्ट क्रिस्टोफ

(2) सेन आर्क लैण्ड, मोन्सैरान, सेमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह।

- (3) अजमन, दुबई कुजाइरह, राम अल सेमाह शरजाह और उमजल बवेयेन।
- (4) अदन और विभिन्न मल्लनत और अमीरान सहित।
- (5) सोसायटी आई लैड्स समूह (ताहिरी सहित) को शामिल करने हुए आस्ट्रेलिया द्वीप समूह, दुधामोट, जाम्बियर एण और माकोमन द्वीप समूह।
- (6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कांगोलीन द्वीप समूह मार्शल द्वीप समूह और मैरिना द्वीप समूह (गाम की छोड़ कर)।

(क) 2 ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश:

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतन्त्र
गैबोन
नाइजीरिया
इक्वेटोर
बेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कतर
सऊदी अरब
आबुधाबी
इण्डोनेशिया

अनुबंध-2

ओ०ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण को अधीन मान और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए सूक्ष्म मार्ग दर्शन।

1. विज्ञापन:

औपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होनी चाहिए।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं:

2.1 बोली बांड और गारंटियां:

बोली बांड या बोली को गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साहित हो जाएं। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली बांड अथवा गारंटियां अमफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें:

संविदा के प्रस्तावन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में अत्यन्तक और ठेकेदार या संभरक को अधिकार और बाध्यत्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परस्परगत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है कि अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किम्प और आकार:

संविदाएं, निष्पादन काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदिन मनों के या एक मूल्य कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के

लिए दोनों के समझ के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है या और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चर्चा गई संविदा की किम्प की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।

वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः, आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है।

इंजीनियरिंग, उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक:

वे नियंत्रक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान ऋण की रकम में से किया जाना है। (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे:—

- (1) अधिदान किए गए शेषों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निवेशकों का बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) ऐसे स्थायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3. संविदा की कीमत:

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए, बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा। ऋण की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन धाराएं:

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है।

यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमत में समंजन के लिए व्यवस्था होना चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए।

माल की मन्वार्ड के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन मिलावट के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुधरे किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए।

ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभाव नहीं कराते हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा:

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किम्पों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित त्रय आदेशों और भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संधिदा में संरक्षक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

“मैं (हम) एतद्वारा यह उल्लेख करने है कि मेरी (हमारी) कम्पनी पात्र संरक्षक है, क्योंकि जेवरों का प्रतिशत (%) (पात्र खोन देश) के राष्ट्रियों द्वारा रखा गया है, और प्रतिशत (.....) निवेशक (पात्र खोन देश) के राष्ट्रिक है और मेरी (हमारी) कम्पनी (पात्र खोन देश) में पंजीकृत करवाई गई है।

4.1 मान दंड :

यदि उन राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या मास है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान श्रौद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड को पूरा करने वाली पथ्य वस्तुएं जो मापदण्डों की क्रांति के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 ग्राण्ड नामों का प्रयोग :

यदि निम्न प्रकार के फालतु पुर्णों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ काम आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल ग्राण्ड, नाम सूचो, संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पथ्य वस्तुओं के अस्तित्वों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती हैं और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

4.3 गारंटी निष्पादन बांड और रोक रखा गई धनराशि :

विभिन्न कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की और परिमाण के अनुसार भिन्न भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संधिदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली दस्तावेज में निरूपित किया जाना चाहिए।

भाल श्री सप्ताह के लिए संधिदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखा गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखा गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निदिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाना है तो वह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होता चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली अति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या मुपदेमी में देर होने के कारण फालतु खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली अति से सम्बन्ध प्राप्त शामिल होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा संधिदा में निदिष्ट समय पर अथवा उससे पहले सिविल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने के लिए भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति :

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संधिदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करने हुए इस संबंध में धाराएं होनी चाहिए कि संधिदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने बायस्कों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक बिगड़ करने वाली स्थितियों में फॉर्ल मेन्टोर के फलस्वरूप हुई है (संधिदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)।

7. अगुओं का निपटान :

अगुओं के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संधिदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए 'समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों' पर वाध्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संरक्षक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होने चाहिए।

8. भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा दस्तावेज में वापसी आए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाय कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1 बोलियों के आमंत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय :

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकतर संधिदा को महत्त्व और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। किन्तु, अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रिया विधि :

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि, समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले धाम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों को कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसकी रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन :

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बोली के मूल तत्व में कोई परिवर्तन आए बिना ही केवल स्पष्टीकरण को ही स्वीकार किया जाए। आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली के आस्तविक एवं मूल परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखा जाने वाली क्रियाविधि :

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली को खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिकाशियों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रिया विधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं हैं तब तक नहीं बताया जाना चाहिये जब तक कि सफल बोलीकार के विषय संधिदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जाँच :—बोलियों के छुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि क्या कोई बोलियों के परिकल्पन में त्रिव्य संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली वस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या वस्तावेज विशिष्ट वस्तावरित हैं और क्या बोलियाँ सामान्यता अक्षरों के रूप में सही हैं। यदि बोलियाँ मूल रूप से विशिष्टीकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अक्षरीकृत गलतियाँ हैं या अक्षरों के रूप से बोली संबंधी वस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अक्षरीकृत किया जाना चाहिये। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिये और बोलियों के मिलान के लिये तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिये।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएँ :—पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिये कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिये क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अक्षरीकार कर दिया जाना चाहिये।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलावट :—बोलियों का मूल्यांकन बोली वस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिये। गणितोप गलतियों के लिये समंजित बोली की कीमत के अनिश्चित अल्प भागों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य-कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिये। जहाँ तक संभव हो वे शर्तें बोली वस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानव संकेत के अनुसार रुपये पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहियें। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिये वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिये।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अक्षरों मुद्रायें जिनमें मूल्य चुकाने का प्रस्ताव किया जाता है तो बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जायेगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिये और इसका उल्लेख बोली वस्तावेजों में भी होना चाहिये। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिये विनियम की दर सरकारी स्तर द्वारा प्रकाशित बिक्रय दरों पर होनी चाहिये और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाये तब तक बोलियाँ छुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिये। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिये।

9.8 बोलियों को अक्षरीकृत करना :—बोली वस्तावेजों में सामान्यतः यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अक्षरीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अक्षरीकार नहीं करना चाहिये और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टीकरण पर नई बोलियाँ आमंत्रित नहीं की जानी चाहिये। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अक्षरीकार करने के लिये भी तब अधिवृत्ति देने चाहिये जहाँ (क) बोलियाँ, बोली वस्तावेज के आगम के अनुसार नहीं हैं या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अक्षरीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिये कि वह उस कारण या उन कारणों को पुनरीक्षा करे जिससे अक्षरीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टीकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिये मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिये किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय :—संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिये किया जाना चाहिये जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टीकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिये या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिये जिम्मेदारी ले।

अनुबन्ध- 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र
संख्या दिनांक

सेवा में,

सहायता सेवा तथा सेवा परीक्षा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय,
प्राथमिक कार्य विभाग,
यू०सी०धो० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता---)
के अन्तर्गत जापान से-----का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता)
के अधीन से के
आयात के संबंध में (बैंक का नाम)
को कि वही होना चाहिये जो नीचे (ड) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के
नाम में साक्ष पत्र खोलने के लिये दिया गया है, को प्राधिकार पत्र जारी
करने के लिये आपकी निम्नलिखित धीरे प्रस्तुत करने हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्वीत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)
- (ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमिशन की धनराशि (येन में)
- (झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिये प्राधिकार पत्र मांगा गया है।
- (ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक
- (ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :—
 - (1) राष्ट्रिकता
 - (2) पात्र स्वीत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिये गये शेषों की प्रतिशत

- (3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/वा संभवतः का निश्चयन स्थान
- (4) उन निदेशकों का प्रनिर्णय जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।
- (5) वे भुगतान शर्तें और संभावित शिथिलता जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय हों।
- (6) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।
- (7) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करने समय प्रस्तुत किये जाने वाले वस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)
- (8) पोटलदान अनुदेश (बाह्यनास्तरण पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी हो गई है या नहीं निर्विष्ट कोजिये)
- (9) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (10) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदायें) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत आई०सी०एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुसूच 4

(प्राधिकार पत्र का प्रपत्र)

सं० एक०

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक :

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :- येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार संख्या आई०डी० पी०-16 के अन्तर्गत आयात साख्यपत्र खोलने के लिये प्राधिकरण जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किये गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न व्यौरे के अनुसार सर्वश्री के नाम में येन धनराशि के लिये अपरिवर्तनीय साख्यपत्र खोलने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गये प्रत्येक साख्य-पत्र की प्रति आयातक के बैंक, आई०सी०एफ० भारतीय दूतावास, टोकियो और जूमें एंजलिकित की जाये।

साख्य-पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी तिथि से किया जायेगा। भुगतान के बाद, आई०सी०एफ० को आवश्यक वस्तावेज भेज कर किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिये।

संभरकों को आपके द्वारा किये गये भुगतान की तिथि से और आई०सी०एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिये चुकाये जाने योग्य प्रभार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा आपके द्वारा

भारत में संबंधित आयातक बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किये बिना किया जायेगा, बैंकों के अन्य खर्च जिनमें साख्य-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख्य-पत्रों को जारी रखने के लिये खर्च भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्च भी विदेशी संभरकों को ही देने पड़ेगे और इसलिये आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जायेगा। और इसलिये उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा आई०सी०एफ० में नहीं किया जा सकता। जब और जैसे ही आपके द्वारा भुगतान किया जाता है और आपके प्रतिपूर्ति की जाती है, तो निर्धारित प्रपत्र में इस संवत्सय की सूचना भेजें।

यह प्राधिकार-पत्र समुदायर संभरकों के नाम में साख्य-पत्र खोलने के लिए है। इस संवत्सय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए धागे के नए साख्यपत्र या साख्यपत्र में बाढ़ के संशोधनों का अनुपाधन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. आयातक को उनके पत्र सं० दिनांक के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा से वस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17 जनवरी, 1976 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अवायगी करने की तिथि से सरकार के लेखों में मूल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई-टीसी (पी एन)/76, दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से व्याज को सरकारी लेखों में जमा करना होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरकों को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखों में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो गुरस्त उसकी सूचना दी जाएगी।) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात वस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीम हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1980, संख्या 233-आईटीसी (पी एन) 68, दिनांक 24 अक्टूबर, 1968, सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्टूबर, 1971 सं० 74-आई टीसी (पी एन)/74, दिनांक 31 मई, 1974 और सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12 अक्टूबर, 1976 की शर्तों की ओर दिनाया जाता है। लेखा शीर्ष जिनमें धनराशि जमा का जाएगी वह 'क' डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843-मिबिल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेकट्टा एन्ड अन्डर परचेजिगम क्रेडिट अन्डर लोन एप्रीमेंट येन 1.5 लियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी०पी०-16 फार 1981-82 फोम चि गवरनमेंट आफ जापान है।

जिन मामलों में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्टूबर, 1971 के अनुसार नक़द जमा किया जाता है, उनको धारण की मूल रूप में एक प्रति बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल, यू०सी०पी० बैंक बिल्डिंग,

समद मार्ग, नई दिल्ली-110001।

जिस मामले में मुख्य रूप से उपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 में यथा उल्लिखित दर्शनी दृष्टी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए मुख्य रूप का पूरा भूरा इस विभाग की भेजना चाहिए।

संभरणों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक ओ०ई०सी०एफ० द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को किए गए व्याज प्रसार बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना सीधे ही आपके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

- निदेशक, ऋण विभाग 2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टैकवनी रोडो बिल्डिंग, 4-1, ग्रीनहिलेनी 1-कोमे, जियोडा-कू, टोकियो-100 जानान।
- भारतीय दूतावास, टोकियो।
- अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

सेवा अधिकारी

अनुबंध 5

(ओ०ई०सी०एफ०एल०सी०-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(मान के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

..... यह साख-पत्र (ऋणी) और विदेशी
..... आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए
..... ऋण करार सं०
(संभरण का नाम और पता) के दिनांक के
..... अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी दृष्टी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० खोल दिया है जो येन (..... येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित वस्तावेज के साथ भेजा जाता है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

सलीम भान बोर्ड, समुद्री प्रोत लवान बिल जिसमें किए गए आदेशों का पूरा सेट हो बैंक पुष्ठांकित एवं चिन्हित 'क्रेड' एवं 'नोटिफाई'

अन्य वस्तावेज जिसमें से

तक लवान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा सं० (यदि कोई हो) के संबंध में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलवान स्वीकृत है। बाह्यतरण स्वीकृत है।

पोतलवान बिल जो से बाव की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशिती को डाफ्ट 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी डाफ्ट और वस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० दिनांक 19 के अंतर्गत निकलवाया गया और आयात संबंध सं० (संख्याएं) यदि कोई हो। यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद् द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी डाफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को वस्तावेजों की सुपुर्वी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक प्रत्यक्षा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट 'युनि फार्म नस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाक्यूमेंट्स क्रेडिटस (1974) (रिबीजन) इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स बोचर नं० 290 के अधीन है'।

सीधा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश

1. उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किए गए वचन-पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सीधा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दृष्टी की अनुराशि को सीधा देंगे।

2. सीधा करने वाले बैंक यह बताते हुए हमें डाफ्टस और वस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण-पत्र अवश्य भेजे कि क्षेत्र एस्तवेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के जब आयातकों/संभरणों के लेखों के लिए हैं।

भववीय,

(.....)

वाणिज्यिक बैंक

..... द्वारा
(प्रासिद्ध हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें:

यह भुगतान हमारी साख-पत्र सं० का अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि येन जो, जो कि कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है।

अपेक्षित वस्तावेज:

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि येन जो कि कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है।

अपेक्षित वस्तावेज:

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:

3. पोतलवान वस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि येन जो कि कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है।

टिप्पणी :— पोतलवान वस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न वस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची-७

प्रपत्र श्री० ई० सी० एक०एल०सी०-2

अपरिवर्तनीय साख पत्र
(सेवाओं के लिए लागू)

विनांक

सेवा में,

(संभरक का नाम व पता)

यह साख पत्र (ऋणी) और
विदेशी आर्थिक सहयोग
निधि के बीच हुए ऋण
करार सं० -----
विनांक -----के
अनुसरण में जारी किया
गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए
पूर्ण व्यौरा मूल्य के लिए लाभकारी इन्फ्रस्ट्रक्चर एंड साइड द्वारा उपलब्ध
रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं०
----- जारी किया है जो येन-----
(येन-----पहले) की कुल धनराशि से अधिक
नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा सं०-----
-----और परियोजना -----)
से सम्बन्धित दस्तावेजों की तथी करना है। सीवा तय करने के लिए
इन्फ्रस्ट्रक्चर -----से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी इन्फ्रस्ट्रक्चर और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं०-----
विनांक -----के अंतर्गत भुना लिए गए हैं
से चिह्नित होने चाहिए।

यह क्रेडिट के हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद् द्वारा ध्यान देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों
का अनुपालन करके भुनाए गए सभी इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रस्तुत करने पर और आवे-
शितों की दस्तावेजों की सुपुर्वगी पर विचारणीय किया जाए।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए, यह क्रेडिट
“यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार इन्फ्रस्ट्रक्चर कैपिटल्स (1974 रिवीजन)
इंटरनेशनल बैम्बर आफ कामर्स कोडर सं० 290” के अधीन है

सीवा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत
प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के
पश्चात् इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित
भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के
मामले में, उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की
आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए बचन
बद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपन-
भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम इन्फ्रस्ट्रक्चर की धनराशि को

मोल-मोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार
प्रेषित करने का ध्यान देते हैं।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और
मसीवे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे।

4. इस साख के अंतर्गत बैंक के सभी खर्च आयातकों/संभरकों के
लेखों के लिए हैं।

भगदीय

(आणिज्यक बैंक)

द्वारा -----

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे प्रपत्र साखपत्र सं०-----का
एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान -----
धनराशि -----येन-----
कुल संविदा मूल्य का -----प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज : लाभकारी विवरण
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2. भुगतान वृद्धि
संपूर्ण योग की धनराशि -----ये
कुल संविदा मूल्य का -----प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :-
वेय धनराशि -----अंतिम भुगतान तिथि

येन-----येन-----
पहली किश्त येन-----
दूसरी किश्त येन-----

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी
किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका
एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

विनांक -----

संदर्भ सं० -----

सेवा में,

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ : ऋण करार सं० -----के अंतर्गत -----
परियोजना से संबंधित -----के नाम में-----

येन के लिए -----द्वारा जारी
किए गए साख पत्र की सं० -----विनांक-----

में, अधोहस्ताक्षरी प्रतिनिधि (ऋणी) एतद् द्वारा -----
और -----के बीच संविदा सं० -----
विनांक -----में निहित भुगतान की शर्तों के

अनुसार समुद्र-पार आर्थिक सहयिता निधि द्वारा ----- की
धनराशि ----- केन (यल) प्राप्त करने
के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करना है ।)

(-----)

(सहनी)

द्वारा -----

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न-पत्र में दबाया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 28-ITC(PN)/82

New Delhi, the 31st May, 1982

Subject : Licensing conditions in respect of import of goods and services under the Yen Credit of Yen 1.5 Billion for the implementation of the Hirakud Hydroelectric Project of the Orissa State Electricity Board.

F. No. IPC/23(29)/82.—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of import of goods and services under the Yen Credit of Yen 1.5 Billion for the implementation of the Hirakud Hydroelectric Project of the Orissa State Electricity Board as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMY, Chief Controller of Imports & Exports.

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 28...ITC(PN)/82 DATED THE 31st MAY 1982

Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of Yen 1.5 Billion for the Implementation of the Hirakud Hydroelectric Project of the Orissa State Electricity Board (OSEB) Extended by the Orissa State Electricity Board (OSEB) Extended by the

Section I—General Conditions :

I(i) The Yen Credit of Y 1.5 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Hirakud Hydroelectric Project of the Orissa State Electricity Board (OSEB) is united in favour of the developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 1,700 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also endorses that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P16". The first and second suffix to the licence code will be 'S/IC'. This will also be repeated in

the letter from the CCI&E forwarding the import licence to O.S.E.B., a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of OSEB on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of OSEB more than one import Licence may be issued under this credit but the total value must not exceed Y 1,700 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by OSEB, be granted upto 31-3-86. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vi) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the overseas supplier duly signed by the letter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :—

".....Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-86

Section II —Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should include Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The main guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

- (a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- (b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- (c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- (a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- (b) Whether the number of qualified suppliers is limited.
- (c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- (d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate.

- (i) Formal Selective International Tendering
- (ii) Informal International Competitive Procurement
- (iii) Direct Purchases from a single supplier.

OSEB should submit immediately in triplicate, copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings, reports of the analysis of bids, proposal for awards and all other documents relevant to the bidding to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) who will submit these documents to the OECF for its review as provided in para (12) of Schedule 5 of the Loan Agreement.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P 16 for 1981-82 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

Supplier's FOB Price

and

"I, the undersigned, hereby certify that—

(Name of company) has been incorporated and registered in _____ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries :

Financing of goods which contain in materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae;

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts :

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 15th October, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 16 (Project Aid) for Hirakud Hydroelectric Project of OSEB and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P16 dated 15th October, 1981 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii)

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed both O.S.E.B. and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P.16 (Project Aid) for Hirakud Hydroelectric Project of OSEB.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, O.S.E.B. and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the OSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA & A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA & A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's banker are to be borne by the Overseas suppliers and hence not payable by the importer. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importer's bank in India, by remittances to the Bank of India Tokyo through normal banking channel without affecting the Government India's account.

Section VI—Responsibility for rupee deposit :

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9% per annum for the first 30 days and @ 15% per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC (PN)/74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC (PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credit/Loans Agreements from the Government of Japan—4 Billion Yen Credit No. ID-P.16 for Hirakud Hydroelectric Project.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)/76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank of India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No.-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA & A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions.

VIII (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licence should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licence the suppliers. The

conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions :—

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 16 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures :

Annexure-I List of eligible source countries.

Annexure-II Broad Guidelines for Procurement.

Annexure-III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-IV Form of Letter of Authority.

Annexure-V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE—III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

DATE :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U. C. O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi—110001.

Sub :—Import of _____ from Japan under the Yen Credit No. _____ (Project Aid)

Sir,

In connection with the import of _____ from _____ under the above mentioned Yen Credit No. _____ (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the _____ (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- Name and Address of the Indian Importer.
- Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- Brief description of the goods.
- Origin of the goods.
- Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- Gross FOB value of contract (in Yen) Authority is required.
- Amount of Indian agents commission (in Yen): if any.

(i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier :

(i) Nationality

(ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transshipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O. E. C. F.

ANNEXURE-IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
New Delhi, the.....

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ID-P 16—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you, for the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, shall be settled by you with the concerned importers' bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers

if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and any therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto- ———

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to:-

1 Importer-————— with reference to their letter No. ——— dated ———

2. Importers Banker-————— They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8 ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9% per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 46 ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184 ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233 ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132 ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74 ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103 ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is 'K Deposits & Advances-843-Civil Deposits-Deposit for purchases etc abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements Loans from the Government of Japan 1.5 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.16 for 1981-82

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132 ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

271 GI/82 --3

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the dates of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director Loan Department II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda Ku, Tokyo 100, Japan,

4. Embassy of India, Tokyo

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

ANNEXURE-V

Form: OECF-LC-I

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date:

To ——— This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ———

dated ———
(Name and address of the Supplier) between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. ——— in your favour for account of ——— for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of ——— (Say yen ———) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in ———
Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and "Notify" ———

Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. ——— (if any) from ——— to ———
Partial shipments are ——— permitted Transshipment is ——— permitted.

Bills of lading must be dated not later than ———
Drafts must be presented for negotiation not later than ———
All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under ———

irrevocable credit No. _____, dated _____
and Import Reference No. (s) _____
(if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank:

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____.
3. All banking charges under this credit are for the account of importers/suppliers.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By: _____

(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount: _____
being _____ % of the total contract price.

Required documents:
Latest presentation date:

II. Intermediate Payment (if any)

Amount: _____
being _____ % of the total contract price.

Required documents:
Latest presentation date:

III. Payment against Shipping Documents

Amount: _____
being _____ % of the total contract price

Note: This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE—V

Form OECF-LC: II

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

To _____ Date: _____

_____ This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____, dated _____, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sum; not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen _____) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents in accordance with the Payment Schedule attached hereto, _____ concerning (Contract No. _____ with regard to _____ Project) Drafts must be presented for negotiation not later than _____

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated _____"

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank:

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the imports/supplies.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By: _____
(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount: _____
being _____ % of the
Total contract price

Required documents: beneficiary's Statement
Latest presentation date: _____

II. Progress Payment

Aggregate amount: _____
being _____ % of the total
contract price to be paid as follows:

	Amount due	Latest presentation
1st instalment:	_____	_____
2nd instalment:	_____	_____
.....	_____	_____

Required document: a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto

Statement of Performance

Date: _____
Re No. _____

To

(Name and address of the
Supplier)

Re: Letter of Credit No. _____, dated _____
issued by _____
for _____ in favour of
_____ concerning _____ project
under Loan Agreement No. _____

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of _____ (Yen _____ only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. _____, dated _____, between _____ and _____.

By: _____
(Borrower)
(Authorized Signature)

Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories : (a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomey
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

III. AMERICA, North and Cent.

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

(Continued)

West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India

Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East :

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA :

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. Europe :

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC :

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

(1) Main Islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main Islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE-II

Man Guidelines for Procurement of Goods and Services under the Project Loans as formulated by O.E.O.F.**I. Advertising :**

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts :**II-1. Bid Bonds or Guarantees :**

Bid bonds or bidding guarantees are as usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract :

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract :

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as ——— percent () of the shares and held by nationals of ——— (eligible source country), and ——— percent () of the directors are nationals ——— (eligible source country) and my (our) company has been registered in ——— (eligible source country)".

IV-1. Standards :

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

271 GI/82-4

IV-2. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money :

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage :

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or less of other benefits to the borrower. Provisions may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation :

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening Evaluation and Award of Contract :

IX. 1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids :

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential :

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids :

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders :

In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids :

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract :

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.